आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव अँचल

वर्ष 47 अंक 37 (प्रति रविवार) इंदौर, 02 जुन से 08 जुन 2024 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

पीएम मोदी का शपथ ग्रहण 9 जून को

भाजपा के जीते मंत्री होंगे रिपीट, सहयोगी पार्टियों की मांग ने बढ़ाई चिंता, 14 सहयोगी दलों के 53 सांसदों को कैसे करेंगे खुश

नई दिल्ली (एजेंसी)। एनडीए की नई सरकार का शपथग्रहण 9 जून को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुछ सांसद रविवार को शपथ लेंगे। इसको लेकर एनडीए में तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा चुनाव में भाजपा के जीते सभी मंत्री इस बार भी रिपीट होंगे। विवाद से जुड़े चेहरों के नाम मंत्री पद की लिस्ट से काटे जा सकते हैं। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर को अहम बैठक हुई। इसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में नई सरकार बनाने, भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने और शपथ ग्रहण की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की खबर है। उधर, खबर है कि एनडीए में लोकसभा अध्यक्ष को लेकर भाजपा, जदयू और टीडीपी में पावरगेम शुरू हो गया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। यह बहुमत के आंकड़े (272) से 32 सीटें कम हैं। हालांकि, एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। एनडीए में भाजपा के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद हैं। गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जदयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी हैं। इनके बिना भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल है। इसको देखते हुए दोनों पार्टियों ने अपने सांसद को लोकसभा अध्यक्ष बनाने की मांग की है।

वहीं भाजपा चाहती है की स्पीकर की कुर्सी उसके पास रहे-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब सबका साथ चाहिए। क्योंकि 2014 और 2019 में तो भाजपा के पास बहुमत की 272 से ज्यादा सीटें थीं। लेकिन इस बार भाजपा की गाड़ी 240 पर अटक गई है। हालांकि, ये साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 9 जून को शपथ लेंगे। लेकिन तीसरी बार एनडीए की सरकार में नरेंद्र मोदी को जिन दो पार्टियों की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनमें एक है तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के चंद्रबाबू नायडू और दूसरी है नीतीश कुमार की जेडीयू। इन दोनों पार्टियों के पास 28 सांसद हैं और पांच साल तक एनडीए की सरकार बनाए रखने के लिए इनका साथ जरूरी बन जाता है। नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, एनडीए सरकार में कई अहम पद चाहती हैं। नीतीश कुमार ने जहां चार सांसदों पर एक मंत्री का फॉर्मूला दिया है। तो वहीं टीडीपी ने सडक़ परिवहन, स्वास्थ्य और कृषि जैसे बड़े मंत्रालय मांगे हैं। इसके साथ ही टीडीपी की नजर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर है।

राहुल बोले- मोदी-शाह ने निवेशकों के 30 लाख करोड़ डुबाए, ये बहुत बड़ा स्कैम

भाजपा ने कहा- लोग निवेश ना करें, राहुल इसके लिए बोल रहे

नई दिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने इसकी जेपीसी (जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी) से जांच कराने की मांग की है। राहुल ने कहा कि 31 मई को भारी स्टॉक एक्टिविटी थी। ये वो लोग थे, जो जानते थे कि कोई न कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ों यहां इन्वेस्ट हुए। 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। रीटेल इन्वेस्टर का नुकसान हुआ। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है।

राहुल गांधी ने कहा, पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाली 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, तो शेयर बाजार आसमान पर जाएगा। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी आने की बात कहते हुए लोगों को शेयर खरीदने की सलाह दी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसी तरीके से शेयर बाजार में जोरदार उछाल की बात कही थी।

भाजपा ने कहा- लोग निवेश ना करें, राहुल इसके लिए बोल रहे- भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा, फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है। इस बात से राहुल गांधी परेशान नजर आते हैं। लोग निवेश न करें, इसके लिए बोल रहे हैं। आज से 10 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी, तब भारत का मार्केट कैप 67 लाख करोड़ था। यही मोदी जी को विरासत में मिला था। आज हमारा मार्केट कैप 415 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। इसमें 5 गुना से ज्यादा बढ़त मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों वाले दिन यानी 4 जून को सेंसेक्स में 4389 अंकों (5.74 प्रतिशत) की गिरावट देखने को मिली थी। इससे निवेशकों को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 4 जून को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का ओवर ऑल मार्केट कैप 395 लाख करोड़ रुपए हो गया थे।

एक दिन पहले यह लगभग 426 लाख करोड़ रुपए था।

नए चुने गए सांसदों में से 251 पर क्रिमिनल केस

2019 में यह संख्या 233 थी; 2009 से 2024 तक 124 प्रतिशत बढ़े दागी सांसद

नई दिल्ली (एजेंसी)। 18वीं लोकसभा का रिजल्ट 4 जून को आ चुका है। नए चुने गए 543 सांसदों में से 46 प्रतिशत यानी 251 पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इनमें से 27 सांसदों को अलग-अलग अदालतों से दोषी करार दिया जा चुका है।एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक दागी सांसदों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 2019 में क्रिमिनल केस वाले 233 (43 प्रतिशत) सांसद लोकसभा पहुंचे थे। नए चुने गए 251 सांसदों में से 170 पर बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे केस हैं। भाजपा के 63, कांग्रेस के 32 और सपा के 17 सांसदों पर गंभीर अपराध दर्ज हैं। लिस्ट में तृणमूल कांग्रेस के 7, डीएमके के 6, तेलुगु देशम पार्टी के 5 और शिवसेना के 4 सांसदों के नाम हैं। तीन सांसद, जिन पर सबसे ज्यादा केस- संसद पहुंचने वाले सबसे दागी सांसदों की बात करें तो केरल की इडुक्की सीट से कांग्रेस के डीन कुरियाकोस का नाम सबसे ऊपर है। डीन ने 1.33 लाख वोट से जीत हासिल की है। उन पर करीब 88 मामले दर्ज हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम कांग्रेस के शफी परम्बिल का और तीसरा नाम बीजेपी के एतेला राजेन्द्र का है।

महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल 15 सांसद- 2024 का चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे सांसदों में से 15 ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों की घोषणा की है। इनमें से 2 पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप है। इनके अलावा, 4 सांसदों ने अपहरण से जुड़े मामले डिक्लेयर किए हैं। 43 ने अभद्र भाषा से जुड़े मामले अपने चुनावी हलफनामे में लिखे थे।

संपादकीय

सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने न्यूज़ चैनलों और प्रिंट मीडिया को दिखाई अपनी ताकत

भारत का लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया है। इस चुनाव में डिजिटल मीडिया(सोशल मीडिया) ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। सत्तारूड दल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल और प्रिंट मीडिया के भरोसे रहा सरकार की गुणगान करता रहा। सरकार और आम मतदाताओं तक सरकार के दावों को पहुंचाता रहा। वहीं डिजिटल मीडिया यूट्यूब के 46 करोड लोगों तक सत्य एवं सूचनाओं को भी प्रमुखता के साथ पहुंचाता रहा। सोशल मीडिया के यूट्यूब प्लेटफार्म पर ऐसे पत्रकार थे, जो सूचनाओं का सही विश्लेषण कर रहे थे। वहीं ऐसे भी लाखों लोग थे, जो सूचनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे थे। लगभग दो माह चुनाव अधिसूचना जारी होने से लेकर चुनाव संपन्न होने तक सोशल मीडिया और भारत के लगभग 230 टीवी चैनल तथा 5500 दैनिक समाचार पत्रों के बीच अघोषित युद्ध चलता रहा। जब चुनाव परिणाम आए उससे यह साबित हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में डिजिटल मीडिया (सोशल)के माध्यम से विपक्ष की लड़ाई जनता और निर्भीक पत्रकारों ने सच को सामने लाने का काम किया। उसका असर इस चुनाव में देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव में इस बार करीब 97 करोड़ मतदाता थे। इन तक जनमत बनाने और सभी किस्म की सूचनाओं को पहुंचाने का माध्यम सोशल मीडिया बना। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की भ्रष्टाचार वाली छवि और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा जो युद्ध सोशल मीडिया के माध्यम से उस समय लड़ा गया था। उसका बड़ा प्रभाव हुआ था। कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों को राष्ट्रीय स्तर पर ?विशेष रुप में हिंदी भाषी राज्यों में बड़ा नुकसान हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में स्थिति पूरी तरह से बदल गई। सरकार का दबाव सभी 230 टीवी चैनल तथा अधिकांश बड़े छोटे समाचार पत्रों में समाचार में क्या छपेगा। इसका अप्रत्यक्ष दबाव होने से न्यूज़ चैनल और प्रिंट मीडिया वही दिखा, या छाप रहे थे। जो सरकारी तंत्र द्वारा उन्हें कहा जाता था। 1975 में जब आपातकाल लगा था और सेंसरशिप लगाई गई थी। उस समय आम जनता तक सही समाचार नहीं पहुंच रहे थे। आपातकाल की समाप्ति के बाद जब सेंसरशिप को खत्म किया गया। उसके बाद आम जनता में विशेष रूप से हिंदी भाषी राज्यों में प्रिंट मीडिया का बड़ा असर हुआ। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को सरकार हिंदी भाषी राज्यों में बुरी तरह से पराजित हुई। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी। लगभग वही स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली। इसमें जितने भी न्यूज़ चैनल और समाचार पत्र थे वह सरकार की ठकुर-सुहाती कर रहे थे। सरकार और जनता को वास्तविकता नहीं बता रहे थे। जिसके कारण आम मतदाताओं का भरोसा टीवी चैनल और समाचार पत्रों में कम हो गया। उसके स्थान पर यूट्यूब और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्म में आम जनता तक स्वतंत्र पत्रकारो द्वारा सत्य को पहुंचाने का काम किया। उसका असर आम मतदाताओं के बीच में देखने को मिला। इस बार उत्तर भारत और सीमावर्ती विभिन्न राज्यों में भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा है। मोबाइल फोन अब संचार का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है।

अब भी मोदी सबसे बड़े एवं वर्चस्वी नेता हैं

ललित गर्ग

अठाहरवीं लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही अपने अंदर कई संदेशों को समेटे हुए हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, भले ही इंडिया गठबंधन एक चुनौती के रूप में खड़ा हुआ हो, फिर भी तीसरी बार नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हुए नये भारत एवं सशक्त भारत को निर्मित करने के लिये वे पहले दो कार्यकाल से अधिक शक्ति, संकल्प एवं जिजीविषा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीटों के लिहाज से भाजपा को भले ही नुकसान हुआ, लेकिन लगातार तीसरी बार वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ओडिशा और तेलंगाना में पार्टी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको चौंकाया है। ओडिशा में लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी पार्टी ने बीजू जनता दल का 24 साल से चला आ रहा वर्चस्व तोड़ा। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 54 प्रतिशत मत और 46 सीटों के प्रचंड बहुमत के बल पर भाजपा सरकार बनाने में सफल हुई है। वहीं, गुजरात, छतीसगढ़ और मध्य प्रदेश भाजपा के गढ़ बने हुए हैं, जबकि देश की राजनीति में अब भी मोदी सबसे बड़े एवं वर्चस्वी नेता है। वे अब भी अपने चौंकाने वाले एवं आश्चर्य में डालने वाले विलक्षण एवं अनूठे फैसलों से राष्ट्र को विकास की नई उड़ान देते रहेंगे। भाजपा को कम सीटें मिले कारणों की समीक्षा एवं मंथन करते हुए अपनी हार के कारणों को सहजता एवं उदारता से स्वीकारना चाहिए एवं जिन गलतियों के कारण कम सीटें मिली, उन्हें दूर करना चाहिए।

इस बार के चुनाव को नियोजित एवं प्रभावी तरीके से सम्पन्न करने में चुनाव आयोग की भूमिका सराहनीय रही। भले ही इडिया गठबंधन ने ई.वी.एम. और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगाकर देश एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कलंकित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम ने न केवल इस प्रकार के भ्रामक, गुमराह करने वाली बातों एवं मिथकों को तोड़ दिया, बल्कि इसने भारत के जीवंत, बहुलतावादी, पंथनिरपेक्षी और स्वस्थ लोकतांत्रिक छवि को पुनर्स्थापित किया है। प्रधानमंत्री मोदी का अंधविरोध करने वाला वाम-जिहादी-सम्प्रदायवादी राजनीतिक समूह अपने इस वाहियात प्रलाप एवं राष्ट्र-विरोधी षड़यंत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिये चुनाव परिणाम अनेक अर्थों में संतोषजनक रहे हैं। कांग्रेस के लिये यह चुनाव नये जीवन का वाहक बना हैं। वैसे भी एक आदर्श लोकतंत्र के लिये सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है, यही लोकतंत्र को खूबसूरती देता है। भारतीय मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को विपक्षी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने का संदेश दिया है।

इस बार के चुनाव परिणाम अनेक राजनीतिक दलों के सामने भी अनेक प्रश्न खड़े किये हैं। कौन जेल में रहेगा, इसका फैसला अदालतें करती हैं। परंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव को अपने जेल के अंदर रहने या बाहर रहने का अधिकार मतदाताओं को सौंपा था, जिसका नतीजा यह रहा कि उनके शासित वाले दिल्ली में 'आप' का खाता तक नहीं खुला, तो वहीं उनकी पार्टी पंजाब में विधानसभा चुनाव-2022 का चमत्कार दोहराने में विफल हो गई और 13 में से केवल 3 सीटें ही जीत पाई। शरद पवार का राजनीतिक वारिस कौन और असली शिवसेना किसकी? क्या माया और ममता अब भी ताकतवर हैं? यह चुनाव ऐसे ही कई सवालों के साथ शुरू हुआ था। इनमें से कुछ के जवाब मिल गए हैं और कुछ के बाकी हैं। जिस तरह के नतीजे आए हैं, उससे यह संदेह भी पैदा हुआ है कि क्या देश में आर्थिक सुधार जारी रहेंगे? क्या देश विकास के पथ पर अग्रसर होता रहेगा? नीतिगत स्थिरता का क्या होगा? शायद इसी संदेह की वजह से शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। लेकिन नरेन्द्र मोदी के पहले भाजपा मुख्यालय में दिये उद्बोधन एवं गठबंधन दलों के साथ हुई बैठक में इन सवालों के जवाब काफी हद तक मिल गये, जिससे शेयर बाजार ने भी तेजी पकड़ी है एवं भाजपा एवं सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है।

देश एक बार फिर गठबंधन सरकारों के युग में प्रवेश कर रहा है। अब यह एक हकीकत है कि मौजूदा जनादेश के मद्देनजर गठबंधन सरकार बनाना भाजपा की मजबूरी हो गई है। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाने और अल्पमत में सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाने में बड़ा फर्क है। सवाल उठाया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत वाले दो कार्यकालों में देशहित के बड़े फैसले लेने वाली भाजपा क्या गठबंधन के सहयोगियों के दबाव के बीच शासन करने में खुद को सहज महसूस कर सकेगी? लेकिन मोदी के नेतृत्व में सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और अपने संकल्पों एवं योजनाओं को आकार देगी, इसमें कोई संदेह नजर नहीं आती। देश में केंद्रीय स्तर 2009 के बाद पहली बार गठबंधन सरकार बनने जा रही है। अतीत में नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन सरकारों का कुशलता से संचालन भी किया है और आवश्यक सुधारों को भी आगे बढ़ाया है। मनमोहन सिंह ने भी दस वर्ष तक गठबंधन सरकार का संचालन किया है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उन्हें किस तरह कई बार सहयोगी दलों के अनुचित दबाव में झुकना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी भी गठबंधन सरकार की चुनौतियों से जूझते रहे। लेकिन मोदी की स्थितियां भिन्न है, वे राजनीति के धुंरधर खिलाड़ी है, अमित शाह राजनीतिक जोड़ तोड़ के खिलाड़ी है, इसे देखते हुए भाजपा और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक अपना काम कर सकेगी, ऐसा विश्वास है। न केवल सरकार बल्कि भाजपा के बड़े मुद्दों का भी क्रियान्वयन होगा। जब-जब भाजपा के सामने अनुचित राजनीतिक दबाव की स्थितियां बनेगी, सरकार कोई सार्थक रास्ता निकाल लेगी।

वैसे भी भाजपा बहुमत के आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि तेलुगु देसम पार्टी, जनता दल-यू, शिवसेना समेत अन्य सहयोगी दलों के साथ उसके लिए सरकार चलाना कहीं अधिक आसान होगा। इसके बाद भी इतना तो है ही कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गठबंधन सरकार का संचालन करेंगे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के तहत कार्य करने के कारण वह ऐसी सरकार के संचालन के तौर-तरीकों से अवगत हैं, लेकिन स्वयं उनके लिए ऐसी सरकार चलाना एक नया अनुभव होगा। लेकिन वे भाजपा संगठन में अनेक पदों पर रहते हुए संगठन की गतिविधियों के कुशल संचालन से भिज्ञ है। देश-विदेश के दबावों को झेलते हुए उन्होंने भारत को एक शक्ति के रूप में खड़ा किया है, दुनिया जब आर्थिक संकट झेल रही है, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, निश्चित ही गठबंधन सरकार का उनका संचालन उनकी नेतृत्व क्षमता और सबको साथ लेकर चलने के राजनीतिक कौशल को एक नया आयाम देगी। उनके पास चुनौतियों के बीच देश की समस्याओं का समाधान करने की एक राजनीतिक दृष्टि एवं कौशल है।

गठबंधन सरकारों के कुछ सकारात्मक पक्ष होते हैं तो कुछ नकारात्मक पक्ष भी। गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने वाले को घटक दलों से समन्वय के साथ चलना होता है। इसमें समस्या तब आती है, जब घटक दल अनुचित मांगें मनवाने लगते हैं अथवा सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति के लिए दबाव की राजनीति करने लगते हैं। इन स्थितियों की निबटने के लिये मोदी सरकार पहले ही अन्य निर्दलयी सांसदों एवं अन्य राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़ने का उपक्रम कर रही है। सहयोगी दल अनुचित मांग एवं दबाव की बजाय अपने राज्य के राजनीतिक एवं आर्थिक हितों की चिंता करें, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें राष्ट्रीय हितों को ओझल नहीं करना चाहिए। यह उन्हें भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गठबंधन सरकार सुगम तरीके से चले।

निश्चित ही मोदी सरकार के सामने चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं, जिस तरह महाभारत युद्ध में पांडवों के सामने जटिल स्थितियां थी। आज द्रोण नहीं तुष्टिकरण है, कृपाचार्य नहीं भ्रष्टाचार है, अश्वत्थामा नहीं आतंकवाद है, दुर्योधन नहीं महत्वाकांक्षा एवं अनैतिकता है, शकुनि नहीं आंतरिक और वैश्विक षड्यंत्र है, राष्ट्रवाद नहीं समस्त प्रकार की विघटनकारी शक्तियां-भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, स्वार्थवाद आदि हैं और कर्ण नहीं कट्टरवाद है। साथ में महंगाई, बेरोजगारी, असंतोष आदि की अत्यंत जटिल समस्याएं भी हैं और अब भारत इनमें फंसा हुआ है। फिर भी नरेन्द्र मोदी रूपी उजाला अपनी नई पारी में अधिक सशक्त होकर भारत के इन सभी चक्रव्यूह को भेदेगा। अपने राजनीतिक जीवन की सबसे सफलतम पारी खेलते हुए वह एक बार फिर नकारात्मक एवं अराष्ट्रवादी शक्तियों को उनकी जमीन दिखायेंगा।

पिपलियापाला तालाब में हुई ऑक्सीजन कम

किनारे पर पड़ी सैकड़ों मछलियां मृत, बदबू से लोग परेशान

इंदौर । पिपलियापाला तालाब का पानी कम होने व प्रदूषित होने का असर अब नजर आ रहा है। तालाब की सैकड़ों मछलियां मर कर किनारे पर आ गई हैं। मरी हुई मछलियों को नगर निगम उठवा भी नहीं पा रहा है। इस कारण बदबू रीजनल पार्क के कई हिस्सों में फैल रही है। तालाब का जलस्तर कम हो गया है। गर्मी के कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। जो मछलियों की मौत की वजह बन रही है।

पिपलियापाला तालाब में बारिश का पानी एकत्र होता है। मार्च तक तालाब का जलस्तर ठीक था, लेकिन बीते दो माह में तालाब का जलस्तर तेजी से कम होने लगा। तालाब में मछली पालन भी होता है। जलस्तर कम होने के बाद तालाब में पानी प्रदूषित होने लगा है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है। पार्क के कर्मचारियों का कहना था कि पहले चार दिन ज्यादा मछलियां नहीं मरी थीं, लेकिन शनिवार से किनारे पर सैकड़ों मरी हुई मछलियां नजर आईं। रीजनल पार्क पर सुबह कई लोग जॉगिंग के लिए आते हैं। उन्हें भी मरी हुई मछलियों की बदबू के कारण परेशान होना पड़ा रहा है।

जल विशेषज्ञों का कहना है कि पानी कम होने के कारण तालाब में गाद के कारण अक्सर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस कारण मछलियां ऑक्सीजन लेने के लिए पानी की सतह पर आती हैं। वहां भी ऑक्सीजन नहीं मिलती है और उनकी मौत हो जाती है। इंदौर में पिछले साल सिरपुर तालाब में भी सैकड़ों मछलियों की मौत हो चुकी थी।

ट्रैफिक पुलिस को बर्थ-डे गिफ्ट ...

छुट्टी के साथ मिठाई का डिब्बा घर पहुंचाते हैं डीसीपी

इंदौर। धूप, बरसात या ठंड हो... ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी बिना छुट्टी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं... इन्हें खुशी और आराम देने का तरीका डीसीपी ट्रैफिक अरविंद तिवारी ने ढूंढा... जिसके बाद परंपरा शुरू हो गई कि जिसका जन्मदिन है, उसे न केवल छुट्टी मिलेगी, बल्कि घर पर मिठाई भी पहुंचेगी।

करीब 715 अधिकारी- कर्मचारियों का अमला है। आमतौर पर हर दिन एक-दो लोगों का जन्मदिन ही आता है और उन्हें छुट्टी मिलती है। हालांकि आज नौ लोगों का जन्मदिन है। सभी को छुट्टी मिली है। इनमें सूबेदार सुरेंद्रसिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक कैलाशचंद्र पंवार, आरक्षक पंकज यादव, आरक्षक प्रियंका मालवीय, आरक्षक जगपाल, प्रधान आरक्षक सुभाष पटेल, आरक्षक रंजू रावत, आरक्षक मनीषा मालवीय और आरक्षक नेहा कुंवर राठौर शामिल है। इन सभी को अधिकारियों की तरफ से कल ही जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं मिल चुकी। वहीं ट्रैफिक पुलिस के वाट्सएप ग्रुप पर जन्मदिन के संदेश भी चल पड़े। इन्हें खास तरह से तैयार किया सिपाही सुमंतसिंह कछावा ने। आज बारी है मुंह मीठा करने की, तो इ तजाम ये है कि दुकान से मिठाई लेकर अमले का ही व्यक्ति संबंधित के घर पहुंचेगा और मुंह मीठा कराएगा।

जन्मदिन पर छुट्टी और मिठाई की इस परंपरा से ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी खुश हैं कि परिवार के बीच वक्त बिताने का मौका मिलता है। घर के लोग खुश हो जाते हैं कि उनके महकमे की तरफ से घर मिठाई भेजी गई है। जन्मदिन की खुशी दोगुना हो जाती है। इससे पहले होता ये था कि जन्मदिन पर भी ट्रैफिक संभालना पड़ता था और घरवाले केक काटने के लिए इंतजार करते रह जाते थे।

ड्यूटी पर बिगड़ी आरक्षक की तबीयत छुट्टी ली अस्पताल में तोड़ा दम

इंदौर। रावजी बाजार में पदस्थ एक आरक्षक की मंगलवार को तबीयत बिगड़ गई। वह छुट्टी लेकर घर चला गया। घर जाने के बाद उसे सीने में और तेज दर्द हुआ। मकान मालिक उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। लेकिन यहां उसकी मौत हो गई। सदर बाजार पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरक्षक का नाम विनोद जाट निवासी मरी माता चौराहा के पास है । वह रावजी बाजार थाने में पदस्थ था। साथियों ने बताया कि उसे सीने में हल्का दर्द हो रहा था। वहीं बेचैनी भी हो रही थी। इसके बाद वह छुट्टी लेकर घर चला गया। लेकिन शाम होते- होते उसकी और तबीयत बिगड़ी। इसके बाद मकान मालिक उसे नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां डॉक्टरों ने सीपीआर दी। लेकिन इससे पहले ही विनोद की मौत हो चुकी थी। विनोद मथुरा का रहने वाला है। उसके परिवार में दो बच्चे और पत्नी हैं। बुधवार को पोस्टमार्टम के पात परिजनों को सौंपा जाएगा।

इंदौर में पहली बार बसपा 51 हजार पार

इंदौर। 1998 में पहली बार इंदौर लोकसभा सीट से मैदान में उतरने वाली बहुजन समाज पार्टी भले ही जीत हासिल नहीं कर पाई हो, लेकिन इस बार उसके उम्मीदवार संजय सोलंकी को 51 हजार से अधिक वोट हासिल हुए हैं, जिससे शहर में तीसरे मोर्चे को बल मिला है। इंदौर में इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होने से कांग्रेस ने नोटा को प्रमोट किया। इसका बहुजन समाज पार्टी को फायदा मिला है। जानकारों का कहना है कि इंदौर में सीमित संसाधनों के बावजूद जितने वोट बसपा को मिले हैं. वो काफी बेहतर हैं। बसपा अगर इस चुनाव को ताकत से लड़ती तो बेहतर परिणाम मिलते। हालांकि इंदौर जैसी सीट पर विजय पाने के लिए बसपा को अभी काफी काम करना पड़ेंगे। इंदौर में बसपा को पहले चुनाव में केवल 984 वोट मिले थे, लेकिन अब इसमें कई गुना वृद्धि हो गई है।

वर्ष बसपा उम्मीदवार प्राप्त मत 2019 दीपचंद अहिरवाल 8666, 2014 धरमदास अहिरवार 7422, 2009 रहीम खान 7226, 2004 कैलाशचन्द्र साहू 10331, 1999 सुरेश यादव 3262, 1998 अख्तर बैग 984।

पिछले महीने टोल टैक्स खत्म

अब ट्रैफिक में बाधक बना नाका तोड़ने का काम भी शुरू

इंदौर । इंदौर के एमआर-10 ब्रिज के टोल टैक्स से 18 साल बाद वाहन चालकों को मुक्ति मिली और अब टोल नाके को भी तोड़ा जा रहा है। टैक्स खत्म होने के बाद कंपनी ने यहां कर्मचारी हटा लिए थे। उसके बाद नाका ट्रैफिक में बाधक बन रहा था। इंदौर विकास प्राधिकरण ने ठेकेदार कंपनी को नाका तोड़ने के लिए कहा था। शनिवार से नाका तोड़ने का काम शुरू हो गया। इस कारण मध्य लेन से ट्रैफिक का आवाजाही रोक दी गई है। नाका तोड़ने में सात दिन का समय लगेगा,क्योकि नाके का पक्का निर्माण किया गया था। पहली मंजिल पर दो बड़े हॉल भी बनाए गए थे। इसके अलावा छत पर बड़ा होर्डिंग भी लगाया गया था। टैक्स वसूलने की समयसीमा खत्म होने के बाद प्राधिकरण अफसरों ने एक माह के भीतर नाका तोड़ने के निर्देश दिए थे,क्योकि ट्रैफिक के बढ़ने के कारण प्राधिकरण पुराने ब्रिज के पास एक और फोरलेन ब्रिज का निर्माण कर रहा है। इसका फिजिबिलिटी सर्वे कराया जा रहा है। तीन साल के भीतर नया ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा, क्योकि वर्ष 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ मेला लगने वाला है। तब सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव इस मार्ग पर ही रहेगा। वर्ष 2004 में सिंहस्थ मेले को देखते हुए इंदौर विकास प्राधिकरण ने चंद्रगुप्त मोर्य प्रतिमा से सांवेर रोड तक सड़क बनाई थी। रेलवे ट्रेक पर तब प्राधिकरण ने ब्रिज बनाने की अनुमति ली थी। तब प्राधिकरण के पास ज्यादा राशि नहीं थी। इस कारण ब्रिज का जिम्मा महू की जिस कंपनी को दिया गया। उसे 18 साल तक टोल टैक्स वाहन चालकों से लेने का अनुबंध प्राधिकरण ने किया था। आठ साल पहले ब्रिज नगर निगम सीमा का हिस्सा बन गया था। इस कारण इंदौर के वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन बाहरी वाहनों से टैक्स लिया जा रहा था।

बच्चों के यौन शोषण पर तत्काल शिकायत करें :

पॉक्सो एक्ट में पुलिस संवेदनशीलता से करेगी कार्रवाई, नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत

भोपाल। *पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन शोषण के अपराधों से बचाने का प्रावधान है। यह कानून न सिर्फ बालिकाओं के यौन शोषण बल्कि नाबालिग लडकों के साथ भी कोई अश्लील छेड़-छाड़ होती है तो उसे भी अपराध की ही श्रेणी में माना जाएगा। इस अधिनियम के तहत दुष्कर्म की पारंपरिक परिभाषा के अलावा उन कृत्यों को भी दुष्कर्म के संज्ञा दी गई है। जिससे बच्चे के साथ गलत भावना से छेड-छाड़ की जाती है।*

12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो दोषी व्यक्ति को मौत की सजा का प्रावधान

यदि किसी व्यक्ति का पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे अपराधी मानते हुए कड़ी सजा देने का प्रावधान रखा गया है। पॉक्सो एक्ट में संशोधन से पहले अग्रिम जमानत का प्रावधान था। लेकिन संशोधन के बाद आरोपी को अग्रिम जमानत भी नहीं दी जाती।

पॉक्सो अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

अगर आप या आपका कोई जानने वाला यौन शोषण का शिकार हुआ है तो आप पॉक्सों एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पहला कदम पुलिस से संपर्क करना और घटना की रिपोर्ट करना है। आप या तो व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन जा सकते हैं या शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आपको घटना की तिथि, समय और स्थान के साथ-साथ यदि संभव हो तो अपराधी की पहचान जैसे विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होगी। पुलिस दुर्व्यवहार के सबूत इकट्ठा करने के लिए पीड़िता की मेडिकल जांच की व्यवस्था करेगी। अगर पुलिस को पता चलता है कि शिकायत पॉक्सो अधिनियम के दायरे में आती है, तो वे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगे और जांच शुरू करेंगे। पॉक्सो अधिनियम के तहत एक नामित अदालत में मामले की कोशिश की जाएगी। पीड़िता और गवाहों को कोर्ट में गवाही देनी होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पॉक्सो अधिनियम पीड़ित और गवाहों की पहचान की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान करता है।

पॉक्सो के तहत पुलिस की जिम्मेदारियाँ

पुलिस इस कानून को लागू करने और ऐसे अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पॉक्सो एक्ट के तहत जब किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध की शिकायत प्राप्त होती है, तो पुलिस को तुरंत शिकायत दर्ज करेगी ।

पुलिस पीड़ित या किसी गवाह के बयान को इस तरह से दर्ज करने के लिए जिम्मेदार है जो बच्चे की उम्र, लिंग और मानसिक स्थिति के प्रति संवेदनशील हो। पुलिस को यह सुनिश्चित करेगी कि अपराध के सबूत इकट्ठा करने के लिए शिकायत के 24 घंटे के भीतर पीड़िता की मेडिकल जांच हो। यदि अपराध में उनकी संलिप्तता का उचित संदेह है तो पुलिस के पास आरोपी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति है।

पुलिस को जांच और मुकदमे के दौरान सुरक्षा और सहायता प्रदान करने सहित पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। पुलिस को अपराध की गहन जांच करनी चाहिए, अपराध से संबंधित सभी सबूतों को इकट्ठा करना चाहिए और उसे कोर्ट में पेश करना चाहिए।

पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्तों का मुकदमा समयबद्ध तरीके से चलाया जाए और उसमें तेजी लाई जाए। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत पुलिस की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

पॉक्सो एक्ट में सजा और नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत

पॉक्सो एक्ट का यह अपराध एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। जिसमें दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान होता है। जो भी व्यक्ति इस अपराध को करने का दोषी पाया जाता है। इस अधिनियम में अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद यह फैसला लिया गया कि अगर कोई 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो दोषी व्यक्ति को मौत की सजा दी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति पर नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण जैसे अपराध करने के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसे किसी भी प्रकार से जमानत नहीं दी जा सकती।

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की हायर स्टडी पीजी पॉलिसी

सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को इस्तीफे की शर्त पर मिलेगी पीजी में दाखिले की एनओसी

भोपाल।सरकारी अस्पताल में 2 साल से कम समय तक कार्यरत रहे डॉक्टर्स को अब नौकरी से इस्तीफा देने के बाद ही इन सर्विस कोटे की सीट पर एडमिशन की एनओसी स्वास्थ्य विभाग देगा जबकि 2 से 5 साल तक की नौकरी वाले डॉक्टर्स को डिग्री कंपलीट होने के सात दिन के भीतर स्वास्थ्य संचालनालय में अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी। ऐसा नहीं करने करने पर संबंधित डॉक्टर की पीजी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी डिग्री की समयावधि को संबंधित की सर्विस बुक में शामिल नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान स्वास्थ्य विभाग ने हायर स्टडी पीजी पॉलिसी 2024 में किए हैं जिसे डायरेक्टर हेल्थ दिनेश श्रीवास्तव ने जारी किया है।

हायर स्टडी पीजी पॉलिसी के नियमों के मुताबिक 2 से 5 साल तक की नौकरी वाले सरकारी डॉक्टर्स को डिग्री कंपलीट होने के बाद पांच साल की नौकरी सरकारी अस्पताल में करने का बांड भरना होगा जो 50 लाख रुपए का होगा। डॉक्टर्स को 50 लाख रुपए का बांड पीजी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी डिग्री कोर्स में दाखिले से पहले भरना होगा। बांड की राशि सरकारी अकाउंट में जमा करने के बाद ही इन सर्विस कोटे की सीट पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की पात्रता एनओसी जारी होगी।

सरकारी डॉक्टर्स के लिए 30 फीसदी सीटें रिजर्व-भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज सहित राज्य के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अलग - अलग स्पेशिएलिटी की 1262 पीजी डिग्री - डिप्लोमा सीट हैं। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अफसरों के मुताबिक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50 फीसदी सीटें ऑल इंडिया कोटे के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व है। जबकि शेष 50 फीसदी सीटों में से 30 प्रतिशत सीटों पर इनसर्विस कोटे के उम्मीदवारों को एडमिशन दिए जाने का प्रावधान है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर्स के लिए रिजर्व पीजी सीटों की संख्या 190 है।

बांड अमाउंट जमा करने पर मिलेगी एनओसी-सरकारी अस्पताल में कार्यरत बांडेड डॉक्टर्स को इनसर्विस कोटे के तहत पीजी कोर्स में दाखिले की पात्रता के लिए इस्तीफे के साथ बांड की राशि जमा करना होगी। इसके अलावा संबंधित बांडेड डॉक्टर के खिलाफ विभागीय जांच और आपराधिक मामला दर्ज होने की स्थिति में इनसर्विस कोटे के सीट की पात्रता के लिए एनओसी नहीं मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित अस्पतालों में सीधी भर्ती से चयनित मेडिकल ऑफिसर (एमओ) और स्पेशलिस्ट को दूसरे डिपार्टमेंट की भर्ती परीक्षा, इंटरव्यू में शामिल हो सकेंगे। लेकिन, इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए संबंधित डॉक्टर को तकनीकी इस्तीफा (टेक्नीकल रिजाइन) देना होगा। इसके बाद ही संबंधित डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग दूसरे विभाग की भर्ती परीक्षा , इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति देगा।

मध्यप्रदेश में 7 साल से नहीं हुई महिलाओं की सुनवाई

शिकायत के 24000 मामले लंबित

भोपाल। *महिलाओं को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार बड़े-बड़े दावे करती है। महिला सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। हकीकत ठीक इसके विपरीत है। मध्य प्रदेश महिला आयोग मे 24000 से ज्यादा शिकायतें आयोग में लंबित है। 2018 से महिला आयोग में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है।*

पिछले 7 साल से महिला आयोग मे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने के कारण, सारी शिकायतें लाल बस्ते में बांधकर रखी जा रही हैं।महिलाएं आयोग के चक्कर पर चक्कर लगा रही हैं।सरकार 7 साल में महिला आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर पाई। यही वास्तविक सच है। 2019 में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी। उस समय शोभा ओझा को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। सदस्यों की नियुक्ति भी की गई थी। 18 माह के बाद सरकार बदल गई है। शिवराज सिंह चौहान की नई सरकार आ गई।भाजपा सरकार ने शोभा ओझा की नियुक्ति को नहीं माना। यह मामला कोर्ट पहुंच गया।सास बहू के झगड़े में हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मध्य प्रदेश में कोई राहत नहीं मिल पा रही है।

महिला आयोग में पिछले 7 साल से सुनवाई नहीं होने के बाद भी,न्याय की आस में 8 से 10 शिकायतें रोजाना महिलाओं द्वारा आयोग में की जाती हैं। यहां पर कहा जाता है, वह अपनी शिकायतों को लेकर संबंधित महिला थाने या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जाएं।महिलाएं यहां से वहां भटकती हैं। इससे अच्छा है, सरकार महिला आयोग के अस्तित्व को ही समाप्त कर दे।

प्रशासन के बाद हाईकोर्ट ने भी प्राइवेट स्कूलो को झटका दिया

दायर याचिका खारिज, राज्य सरकार से 4 हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा

जबलपुर। *हाईकोर्ट ने अवैध फीस वसूली मामले पर प्राइवेट स्कूलों पर की गई कार्रवाई और संचालकों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह याचिका खारिज की है। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है। अवैध फीस वसूली मामले में 11 स्कूलों से जुड़े 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।*

हाईकोर्ट ने कहा कि ये अपराध बेहद गंभीर है और जांच शुरुआती दौर में है। लिहाजा अभी पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से कार्रवाई को लेकर पूरा विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई जुलाई के

सप्ताह में तय की गई है। जबलपुर जिले में प्रशासन ने अवैध रूप से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया था। प्रशासन ने स्कूली किताब की दुकान वालों पर भी कार्रवाई करते हुए 11 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। जबलपुर जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि इन स्कूलों ने चालू शैक्षणिक सत्र में छात्रों से अवैध रूप से 81.3 करोड़ रुपए का शुल्क वसूला है। प्रशासन के एक्शन से प्राइवेट स्कूलों में हड़कंप मच गया।

11 स्कूलों पर 22 लाख जुर्माना

जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना था कि अवैध रूप से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर अधिकारियों ने 11 विद्यालयों पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह का कहना है कि इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिला प्रशासन ने गलतियां पाए जाने के बाद स्कूल पदाधिकारियों और पाठ्यपुस्तकों की दुकानों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की।

कार्यवाही के खिलाफ हाई कोर्ट गए स्कूल संचालक

स्कूल संचालकों ने पुलिस की जांच कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने स्कूल संचालकों के द्वारा अभिभावकों से मांगी गई फीस को गंभीर माना। ऐसे में अब 11 स्कूलों के 21 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात भी कही।

जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर पुलिस-प्रशासन और शिक्षा विभाग ने पूरे जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 60 से अधिक स्कूलों में जांच करवाई, जिसमें 11 स्कूलों की गंभीर लापरवाही पाई थी। अवैध फीस वसूली के अपराध में पुलिस-प्रशासन की जद में आए निजी स्कूल संचालकों की गिरफ्तारी और जांच को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए अवैध फीस वसूली में आरोपी बनाए गए निजी स्कूल संचालकों को राहत देने से इंकार कर दिया है।

पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर

जिला प्रशासन की कार्रवाई के दौरान दोषी पाए गए निजी स्कूल संचालकों ने जांच और पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट में स्कूलों की ओर से कहा गया कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वो जांच में सहयोग करने तैयार हैं लेकिन उन पर पुलिस कार्रवाई न की जाए।

बुक सेलर्स से सांठगांठ कर फर्जी किताबें बेची

शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि स्कूलों ने अवैध रूप से अतिरिक्त फीस ही नहीं वसूली है, बल्कि बुक सेलर्स से सांठगांठ कर फर्जी किताबें सिलेबस में लगाने का अपराध भी किया, जो कि बच्चों का भी अनहित करने जैसा है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि अगर आरोपी स्कूल संचालकों और उनके गठजोड़ पर पुलिस कार्रवाई नहीं की जाती, तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि, पुलिस और प्रशासन को अभी उनके स्कूलों से और भी कई दस्तावेज जब्त करने हैं। इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट जस्टिस विशाल धगट की कोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों को राहत देने से इंकार कर दिया है।

बिना कारण बिजली बंद हुई तो संबंधित इंजीनियर पर कार्रवाई, ऊर्जा मंत्री के निर्देश

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चेतावनी दी कि बगैर किसी जरूरी कारण के बिजली आपूर्ति बंद हुई तो संबंधित क्षेत्र के इंजीनियर के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी यह महसूस करें कि अगर इस गर्मी में उनके घर की बिजली एक घंटे बंद रहेगी तो उनके परिवार को कैसा लगेगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह बात आज मंत्रालय में बिजली ट्रिपिंग और मेंटेनेंस की समीक्षा के दौरान कही। अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) मनु श्रीवास्तव ने भी कहा कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कंपनी के संबंधित क्षेत्र के कार्यपालन अभियंता से लेकर जूनियर इंजीनियर तक मोहल्ले में उपभोक्ताओं के साथ बैठक कर संवाद करें। उन्हें ट्रिपिंग के कारण बताएं। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पुरानी केबल के कारण ट्रिपिंग हो रही है, वहाँ केबल बदलें।

मीटर की रीडिंग निर्धारित दिन ही लें

उन्होंने कहा कि हर माह मीटर रीडिंग निर्धारित तारीख को ही ली जाए। उन्होंने अनुमानित बिल भेजने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि अगर किसी माह में उपभोक्ता का बिल आश्चर्यजनक ढंग से ज्यादा आता है तो उसका परीक्षण करें।

मीडिया में मेंटेनेंस की जानकारी दें

अधिकारियों से ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में बिजली मेंटेनेंस किया जा रहा है, उसकी तारीख और समय की जानकारी विभिन्न समाचार माध्यमों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुँचाएं। वरिष्ठ अभियंता समय-समय पर जनप्रतिनिधियों, किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संगठनों से मिलकर ऊर्जा विभाग की कार्यप्रणाली, समस्याएं और समाधान से अवगत कराएं। फेसबुक, एक्स आदि सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों का भी समाधान किया जाए। हर सर्किल स्तर पर एक टेलीफोन नंबर शिकायत के लिए रखा जाए। इस पर मिलने वाली शिकायतों की मॉनिटरिंग वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाए।

जिनका काम अच्छा उन्हें पुरस्कृत करें

प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली कंपनी के किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा अच्छा कार्य करने पर उसे पुरस्कृत किया जाये। वसूली आदि के दौरान उनके साथ होने वाली मारपीट की घटनाओं पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं

अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) मनु श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। हर हाल में सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। स्थानीय कारणों से बाधित होने वाली विद्युत आपूर्ति का निराकरण समय-सीमा में करें। इस बैठक में ओएसडी विजय गौर, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मध्यस्थता से विवाद समाधान में हर कोई होता विजेता : राज्यपाल मंगुभाई पटेल

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि मध्यस्थता वह प्रक्रिया है, जिसमें हर कोई विजेता होता है क्योंकि मध्यस्थता में विवाद का निपटारा किसी आदेश के द्वारा नहीं होता है, व्यवस्थित चर्चा के द्वारा दो पक्ष समझौते पर पहुंचते है। मध्यस्थता सबके लिए किफायती, जल्द और उत्तरदायी न्याय का सुलभ, सुगम एवं प्रभावी तरीका है। उन्होंने कहा है कि विवाद को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों के समाधान के लिए समाज और सरकार को मिलकर कार्य करना होगा। समाज की विकृतियों को दूर करने के लिए चिंतन करना होगा। बेहतर समाज निर्माण में प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें आगे बढ़कर कार्य करना होगा। राज्यपाल श्री पटेल आज ई-मीडिएशन राईटिंग्स संस्था वर्षगांठ समारोह को संबोधित कर रहे थे।राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विवादों की उत्पत्ति छोटी-छोटी बातों से होती है। बोलने और देखने के तरीकों को लेकर बड़े-बड़े विवाद हो जाते हैं। विवाद बढ़े नहीं, इसके लिए मन-मस्तिष्क की शांति जरूरी है। जरुरी है कि समाज में जागरूकता का ऐसा वातावरण हो, जिसमें सभी हितधारक मध्यस्थता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और पहल का प्रदर्शन करें। युवाओं से अनुरोध किया कि वे जन-सामान्य की बोल-चाल की भाषाओं में मध्यस्थता के अवार्ड के न्यायालयीन महत्व के फ़ायदों को समझाने के लिए आगे आए। समर्थ जन गरीबों, वंचितों को सस्ती, सुलभ और तेज न्याय प्रक्रिया के लाभ दिलाने में मध्यस्थता के द्वारा सहयोग करे।

आई एम डी बी पर दीपिका पादुकोण ने शाहरुक-सलमान ही नहीं ऐश्वर्या को भी छोड़ा पीछे

अब आप सोच रहे होंगे भला बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने ऐसा क्या कर दिया है कि उनसे पीछे तीनों खान रह गए और तो और ऐश्वर्या भी तो बता दें IMDb ने 'मोस्ट व्यूड इंडियन स्टार ऑफ द लास्ट डिकेड' की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में टॉप 100 स्टार्स को शामिल किया गया है। इसमें दीपिका पादुकोण ने सभी को मात देते हुए टॉप स्थान पर जगह बनाई है तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान से लेकर ऐश्वर्या सब पीछे रह गए। IMDb की मोस्ट व्यूज इंडियन स्टार की लिस्ट दुनिया भर के करोड़ों IMDb कस्टमर्स और फैंस के पेज व्यू पर आधारित है। वैसे तो 100 स्टार्स की इस लिस्ट में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स शामिल हैं। मगर टॉप 10 की बात करें तो इसमें दीपिका सबसे ऊपर हैं, उनके बाद इसमें शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट, इरफान, आमिर खान, सुशांत सिंह राजपूत, सलमान खान, ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार के नाम शामिल हैं।

आपको बता दें कि IMDb की टॉप 100 मोस्ट व्यूड इंडियन स्टार्स ऑफ द डिकेड लिस्ट जनवरी 2014 से अप्रैल 2024 तक के डेटा में शामिल हैं। लाजिमी है दीपिका पादुकोण की पॉपुलैरिटी ने उन्हें नंबर वन की पोजीशन पर पहुंचाया है।

दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वह कल्कि 2898 एडी. में नजर आएंगी। इसके अलावा उनकी झोली में सिंघम अगेन भी हैं. वैसे अभी दीपिका पादुकोण अपनी प्रेग्नेंसी पर ध्यान दे रही हैं। इसी साल सितंबर में उनकी डिलीवरी है।

रश्मिका मंदाना ने इंग्लिश में बात न करने पर दिया फैन को जवाब

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने हाल ही में आनंद देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म गम गम गणेशा के प्री-रिलीज इवेंट में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि आनंद देवरकोंडा सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के भाई हैं। इस इवेंट से रश्मिका मंदाना की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियोज में रश्मिका मंदाना को इवेंट के दौरान तेलुगु में बात करते हुए सुना-देखा सकता है। ऐसे में एक फैन ने एक्ट्रेस से अनुरोध किया है और पूछा है कि किसी भी इवेंट में इंग्लिश में क्यों बात नहीं करती हैं, जिसका रश्मिका ने जवाब भी दिया है. इस फैन के ट्वीट का जवाब देते हुए रश्मिका मंदाना ने बताया कि वह फिल्म इवेंट्स में इंग्लिश क्यों नहीं बोलतीं। उन्होंने कहा कि वह अपमानजनक नहीं होना चाहतीं। उन्होंने जवाब देते हुए लिखा, मैं इंग्लिश में बात करने की पूरी कोशिश करती हूं, ताकि आप में से हर कोई मुझे समझ सके, चाहे आप कहीं से भी हों... लेकिन मैं इस फेक्ट को भी जानती हूं कि बहुत से लोग जो चाहते हैं कि मैं उनकी भाषा में बात करूं, नहीं तो वे सोचेंगे कि मैं भाषा का अनादर करती हूं।

जान्हवी कपूर ने शादी की खबरों को लेकर दिया करारा जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर जल्द ही फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही में राजकुमार राव के साथ नजर आने वाली हैं। इस बीच जान्हवी कपूर ने उन अफवाहों पर रिएक्ट किया है जो पिछले कई दिनों से तैर रही थीं। ये खबरें थीं कि जान्हवी कपूर जल्द ही रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया संग शादी कर सकती हैं। अब खुद श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी ने सच बताया है। जानमानी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में, जान्हवी कपूर ने बताया कि उन्होंने उन खबरों के बारे में पढ़ा जहां लगातार ये दावा किया जा रहा है कि वह शादी करने की प्लानिंग कर रही हैं। मगर ये सच नहीं है। वह अभी काम कर रही हैं और अपने काम के लिए काफी पैशनेट हैं।

शादी की खबरों को खारिज करते हुए जान्हवी ने कहा, ' हाल में ही मैंने बहुत ही बेवकूफी वाली न्यूज पढ़ीं। जहां मेरे बारे में लिखा जा रहा है कि मैंने रिश्ता कंफर्म कर दिया है और मैं जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हूं। कुछ लोग तो मेरी एक हफ्ते में शादी भी करवा रहे हैं, जिससे मैं सहमत नहीं हूं. मैं इस समय काम करना चाहती हूं।

ये पहला मौका नहीं है जब जान्हवी ने अपनी पर्सनल लाइफ पर बात की हो। इससे पहले भी अपने रिलेशनशिप की अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी दी थी। कुछ ही दिन पहले पैप्स ने एक पोस्ट किया था जहां कहा गया कि जान्हवी, शिखर पहाड़िया के साथ तिरुपति मंदिर में गोल्ड साड़ी में शादी करेंगी।

सलमान खान की फिल्म सिकंदर में विलेन बन सकते हैं- कटप्पा

साउथ स्टार सत्यराज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की अगली फिल्म 'सिकंदर' में विलेन की भूमिका के लिए चुना गया है। फिल्म का निर्देशन एआर मुरुगदास कर रहे हैं और फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज होने वाली है। पत्रकार और निर्माता चित्रा लक्ष्मणन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सत्यराज फिल्म में सलमान खान के सामने खलनायक की भूमिका निभाएंगे। हालांकि, फिल्म के निर्माताओं ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

गर्मी में साइकिलिंग करते समय रखें कुछ बातों का विशेष ध्यान

बिगड़ती लाइफस्टाइल मोटापे के साथ-साथ कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रही है। ऐसे में इन समस्याओं से बचाव करने के लिए शरीर में कुछ तरह की एक्टीविटी जरूरी है, ताकि शरीर को स्वस्थ्य रखने में कुछ मदद मिल सके। ऐसे में साइकिलिंग एक बेहतरीन एक्टिविटी साबित हो सकती है। साइकिलिंग करके खुद के शरीर को एक्टिव और फिट बनाना आसान हो सकता है। वजह यह है कि इसे भी एक तरह की एक्सरसाइज ही माना जाता है, लेकिन साइकिल चलाने के फायदे क्या-क्या हो सकते हैं। अइये जानते हैं। साइकिल चलाने का सही समय और इससे जुड़ी कुछ अहम बातें बता रहे हैं।

साइकिलिंग का सही समय चुनें

तेज धूप में साइकिलिंग करने न निकलें, इस दौरान न सिर्फ आप जल्दी थक जाएंगे, बल्कि पानी की कमी का शिकार भी हो सकते हैं। बेहतर है कि सुबह जल्दी निकलें या फिर देर शाम, जब सूरज पीक पर नहीं होता।

आराम से करें साइकिलिंग

साइकल चलाते वक्त एक ही तरह की स्पीड बनाने की कोशिश न करें। शुरुआत आराम से करें फिर बीच में बढ़ाएं और फिर स्पीड को हल्की कर लें। लगातर तेज़ी से चलाने के प्रयास में आप खुद को बहुत थका देंगे।

शरीर को हाइड्रेट रखें

अगर आप साइकिल चलाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इससे पहले पानी के अलावा ऐसे फलों और सब्ज़ियों का सेवन भी करें जिसमें पानी की अच्छी मात्रा होती है। सोडियम आपके शरीर को उस तरल पदार्थ को धारण करने में मदद करता है जिसे आप पी रहे हैं, इसलिए साइकिलिंग के दौरान एक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक भी पीते रहें।

पहले से करें तैयारी

गर्मी से आपकी सेहत को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए साइकिलिंग करने की पहले से तैयारी रखें। हाइड्रेशन पैक में कई सारी बर्फ डालें। अगर आप साइकल से लंबा सफर तय कर रहे हैं, तो पहले से पता कर लें कि ठंडा पानी या दूसरे ड्रिंक्स आप कहां से री-स्टॉक कर सकते हैं।

सनबर्न से बचें

साइकिलिंग करने में मजा खूब आता है, लेकिन तेज धूप आपको कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। खासतौर पर त्वचा को, सनबर्न न सिर्फ स्किन को झुलसा देता है, बल्कि ये थकान और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इस समय मेटाबॉलिज्म बढ़ने से आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका शरीर पहले से ही खुद को हाइड्रेट रखने की चुनौती से गुज़र रहा होता है। ऐसे में आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए सनस्क्रीन जरूर लगाएं, जर्सी, शॉर्ट्स और आर्म स्किन सन प्रोटेक्शन वाली चुनें, कैप या हेल्मेट लगाएं।

सिगरेट पीना पुरुषों को पड़ सकता है भारी

क्या आप जानते हैं कि सिगरेट पीने से आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इससे न सिर्फ आपकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता बल्कि स्पर्म काउंट कम होने की भी आशंका होती है।

अगर पुरुष ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो इससे पुरुषों में बांझपन की समस्या हो सकती है। ऐसे में पुरुषों की पिता बनने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। यहां तक आपकी सेक्सुअल लाइफ खराब हो सकती है।

जानें-सिगरेट पीने से कैसे कम होता है स्पर्म काउंट ?

जैसा ही सभी जानते हैं कि पुरुषों के पिता बनने में सबसे बड़ी भूमिका स्पर्म की होती है। ऐसे में स्पर्म जितना ज्यादा हेल्दी होगा, उतना उसकी शादीशुदा लाइफ अच्छी होगी। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिगरेट पीने से पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होता है। इतना ही नहीं इससे स्पर्म की क्वालिटी भी खराब होती है। इसके अलावा पुरुषों के पिता बनने पर भी रोड़ा खड़ा हो सकता है। ज्यादा सिगरेट से बॉडी कई तरह के हार्मोन्स का बैलेंस भी बलते हैं. ये हार्मोनल असंतुलन भी पुरुषों के पिता बनने में अवरोध पैदा करता है।

घर में रखी ये चीजें दिलाएंगी खट्टी डकारों से छुटकारा

आजकल की इस भागती-दौड़ती जिंदगी में खराब लाइफस्टाइल और लापरवाही की वजह से लोग सेहत से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ओवरईटिंग, अधिक तैलीय और मसालेदार भोजन या समय पर खाना ना खाने की वजह से अक्सर लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। इनमें खट्टी डकारें होना एक आम समस्या है। इसकी वजह से कभी-कभी गले, पेट और सीने में तेज जलन का भी एहसास होता है। कई बार तो इसकी वजह से कई बार मूड के साथ-साथ पूरा दिन भी खराब हो जाता है। अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप इन घरेलू नुस्खों के आजमा सकते हैं, इससे आपको राहत मिलेगी।

नींबू पानी – कभी-कभी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही खट्टी डकार आने लगती है। अगर आपको भी ऐसी समस्या होती है तो आप तुरंत एक गिलास नींबू पानी घोलकर पी लें।

मीठी दही – मीठी दही से भी खट्टी डकारों से छुटकारा पाया जा सकता है। इससे आपके पेट को ठंडक मिलेगी और खट्टी डकार की समस्या में भी तुरंत आराम मिलेगा।

सौंफ-मिश्री – सौंफ और मिश्री को एक साथ मिलाकर खाने से भी खट्टी डकारों से राहत पाई जा सकती है। दरअसल, सौंफ पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और पेट में गैस नहीं बनने देता जबकि मिश्री से पेट को ठंडक मिलती है।

हींग – हींग को पाचन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। गैस या खट्टी डकार की समस्या होने पर आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हींग को पानी में घोलकर पी लें, जल्द आराम मिलेगा।

जीरा– जीरा पेट की समस्यायों के लिए एक अच्छा उपचार है। खट्टी डकार, गैस या बदहजमी होने पर जीरे को भूनकर खाने से आराम मिलता है। भुने जीरे को आप दही में डालकर खा सकते हैं। इसके अलावा भुने जीरे के पाउडर को आप सलाद या बहुत सी ड्रिंक्स जैसे आम पन्ना, शिंकजी में डालकर भी पी सकते हैं।

इलायची – खट्टी डकार की समस्या होने पर इलायची का सेवन करने से छुटकारा पाया जा सकता है। पेट की गैस और डकार से राहत पाने के लिए रोजाना समय-समय पर इलायची चबा सकते हैं।

लौंग – लौंग का इस्तेमाल करने से पाचन तंत्र अच्छा बना रहता है। खट्टी डकार की समस्या होने पर लौंग का पानी या लौंग का सेवन करने से फायदा मिलता है।

ग्रीन टी – अपच, खट्टी डकार या पेट से जुड़ी ज्यादातर समस्याओं के लिए ग्रीन टी पीना फायदेमंद हो सकता है।

अदरक – खट्टी डकार की समस्या होने पर आप अदरक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल लें। इसके अलावा आप अदरक का पानी या अदरक की चाय भी बनाकर पी सकते हैं, राहत मिलेगी।

पुदीने की पत्तियां – खट्टी डकार आने पर आप पुदीने की कुछ पत्तियां भी चबा सकते हैं। यह पेट को ठंडक देने के साथ-साथ इस समस्या से भी राहत दिलाएंगी।

सांस और फेफड़ों की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए करें खंड प्राणायाम

खंड प्राणायाम आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद और प्रभावशाली योग है। यह शरीर को मजबूत बनाने के साथ-साथ सिस्टम के फंक्शन को भी प्रभावित करता है। इससे सांस की तकलीफ दूर होती है और फेफड़े भी मजबूत होते हैं। इससे वह बेहतर प्रदर्शन और शक्ति भी बढ़ती है।

-अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो यह प्राणायाम आपके लिए एक बेहतरीन थेरेपी के रूप में कार्य करता है।

-इससे मन और मस्तिष्क में शांति का अनुभव होता है और काम में भी मन लगता है।

खंड प्राणायाम करने का सही तरीका

-सबसे पहले मैट पर दंडासन में बैठ जाएं।

-इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें और कुछ समय के लिए गहरी सांस लें।

-फिर अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करें और अभ्यास के लिए अपने दिमाग को एकाग्र करें।

-इसके बाद खंड प्राणायाम करने के लिए आप पूर्ण पद्मासन आदर्श मुद्रा में बैठ जाएं।

-अब अपनी पीठ को सीधा करें और अपनी आंखें बंद करें।

-उसके बाद अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें।

-अपनी सांस को दो बराबर भागों में बांटते हुए गहरी सांस लें। इस दौरान ध्यान को एक जगह केंद्रित करें।

-अपने फेफड़ों में सांस को रोके बिना दो बार सांस छोड़ें। इस लय को बनाए रखें।

सावधानियां

-हाई ब्लड प्रेशर होने पर न करें। इससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है।

-पीठ में गंभीर दर्द और गर्दन में अकड़न होने पर भी न करें।

-हृदय संबंधी समस्याएं होने पर भी न करें।

-पाचन संबंधी समस्याएं जैसे गैस, अपच और ऐंठन , सर्जरी या ऑपरेशन कराया है, तो अभ्यास न करें।

भी कर पाते हैं। दरअसल खंड प्राणायाम में पहले दो की गिनती तक एक गहरी सांस लें, फिर दो की गिनती तक पूरी तरह से सांस छोड़ें। यह एक सेट पूरा करता है। बिना ब्रेक लिए लगातार इसका अभ्यास करें।

खंड प्राणायाम के लाभ

- खंड प्राणायाम की मदद से स्टेमिना बढ़ाने और एक्सट्रा फैट को बर्न करने में मदद मिलती है।

-इसके अभ्यास से ऑक्सीजन लेने की फेफड़ों की क्षमता का विकास होता है

शंकर लालवानी ने दर्ज की देस में सबसे बड़ी जीत

12 लाख 26 हजार 751 वोट प्राप्त

नोटा ने रचा नया क्रीतिमान, इंदौर में 2 लाख 18 हजार 355 मत मिले

इंदौर । मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीट इंदौर में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी देशभर में सबसे ज्यादा मत हासिल करने वाले उम्मीदवार बने हैं। उन्होंने 12 लाख 26 हजार 751 वोटों से जीत हासिल की है। कलेक्टर आशीष सिंह ने उन्हें प्रमाणपत्र सौंपा है। इंदौर के इतिहास में पहली बार है कि कांग्रेस मैदान में नहीं है। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस ने नोटा को प्रमोट किया था। ऐसे में नोटा ने भी इस बार एक नया इतिहास रचा है। नोटा को इंदौर में 2 लाख 18 हजार 355 मत मिले हैं। बता दें कि इंदौर में नोटा दूसरे नंबर पर मुकाबले में है। लेकिन नियमों के मुताबिक जीत के अंतर में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। तीसरे नंबर पर बसपा के संजय सोलंकी हैं, उनमें और लालवानी को मिले वोटों में दस लाख से ज्यादा का अंतर है, इसे ही जीत का मार्जिन माना जाएगा।

भाजपा नेता ने रचा नया इतिहास

भाजपा के शंकर लालवानी इंदौर में शानदार जीत हासिल की है। ये अब तक के इतिहास की सबसे बढ़ी जीत मानी जा रही है। इससे पहले 2019 में गुजरात के नावासार सीट पर भाजपा के सीआर पाटिल ने 6,89,668 वोटों से अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। इंदौर में भाजपा के शंकर ललवानी के अलावा कुल 13 और प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें प्रमुख प्रत्याशी के तौर पर कोई भी मौजूद नहीं था। इंदौर भाजपा का गढ़ माना जाता है और यहां पिछले कुछ दशकों से भाजपा लगातार विजय दर्ज कराती आ रही है।

प्रत्याशी ने जीत का श्रेय दिया पीएम मोदी को

रिकॉर्ड मतों से जीत को लेकर बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने कहा कि ये जीत पीएम मोदी की नीतियों की जीत है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जीत है। ये इंदौर की जीत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नोटा के लिए आह्वान किया था लेकिन उन्हें पिछले बार की तुलना में आधे भी वोट नहीं मिले। जबकि भाजपा ने पिछली बार से अधिक वोट प्राप्त किए और जीत हासिल की है। कांग्रेस का प्रत्याशी भी यदि सामने होता तो हमे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे नेतृत्व और संगठन ने कड़ी मेहनत की थी।

ये रिकॉर्ड टूटने वाला नहीं है- विजयवर्गीय

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह पीएम मोदी की नीतियों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जीत है। इसका असली श्रेय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जाता है क्योंकि उनकी कड़ी मेहनत से ही बीजेपी ने ये जीत हासिल की है। वहीं, यदि नोटा पर रिकॉर्ड मतों की बात करते है तो आपको शंकर लालवानी की इस जीत के रिकॉर्ड की भी बात करना चाहिए। यह जीत रिकॉर्ड जीत है, जो कभी टूटने वाला रिकॉर्ड नहीं है। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करने का मतलब प्रदेश की जनता पीएम मोदी को बहुत प्रेम करती है।

नोटा ने रचा नया किर्तीमान, इंदौर में 2 लाख 18 हजार 355 मत मिले

नोटा यानी इनमें से कोई भी नहीं के नाम अब तक 51,660 वोट मिलने का रिकॉर्ड है। वहीं इंदौर में नोटा को 2 लाख 18 हजार 355 मत मिले हैं। बता दें कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 'नोटा' को बिहार की गोपालगंज सीट पर सर्वाधिक वोट मिले थे। तब इस क्षेत्र के 51,660 मतदाताओं ने 'नोटा' का विकल्प चुना था और 'नोटा' को कुल मतों में से करीब पांच प्रतिशत वोट मिले थे।

मीडियाकर्मी के साथ मारपीट करने वाले सतीश भाऊ कोर्ट में हुआ पेश

इंदौर में होने के बाद भी बाणगंगा पुलिस नहीं पकड़ सकी

इंदौर। मीडियाकर्मी के साथ मारपीट करने वाले कुख्यात बदमाश सतीश भाऊ ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बाणगंगा पुलिस उसे कई दिनों से तलाश कर रही थी, लेकिन वह इंदौर में होने के बाद भी पुलिस को नजर नहीं आया। बाणगंगा पुलिस की निष्क्रियता के चलते क्षेत्र में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। टीआई लोकेशसिंह भदौरिया अपराधों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। करीब सात दिन पहले एमआर-10 के समीप निर्वाणा गार्डन में नंदानगर निवासी हेमंत यादव के बेटे का विवाह समारोह था।

समारोह में शामिल होने वरिष्ठ पत्रकार अंकुर जायसवाल भी पहुंचा था। वे समारोह से बाहर निकल रहे थे, तभी कुख्यात बदमाश सतीश भाऊ, गब्बर चिकना, अमित जादौन आदि ने उनके साथ जमकर मारपीट की थी। मारपीट के मामले में बाणगंगा पुलिस ने आरोपियों पर प्राणघातक हमले का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी।

पुलिस आरोपियों को तलाश रही थी. इसी बीच तीन दिन पहले मारपीट करने वाले अमित, आशीष और उसके साथी ने थाने में सरेंडर कर दिया था, जबकि पुलिस ने उन्हें भंवरकुआ क्षेत्र से पकड़ना बताया था। मंगलवार सुबह 11 बजे सतीश भाऊ ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जानकारी लगने पर पुलिस कोर्ट पहुंची, तब तक कोर्ट ने भाऊ को सीआई जेल भेज दिया था। यहां से पुलिस खाली हाथ लौट आई।

इंदौर के समीर शर्मा को दुबई में मिला देवी अहिल्या बाई सम्मान

इंदौर। शहर के समीर शर्मा को संयुक्त अरब अमीरात में एक गरिमापूर्ण समारोह में इंडियन पीपल फोरम द्वारा इसी वर्ष से प्रारंभ हुए देवी -अहिल्याबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस समारोह में आईपीएफ चैयरमेन जीतेन्द्र वैद्य, भारतीय कौन्सेल्ट ब्रिजेन्द्र सिंह ने यह सम्मान कुल 8 महिलाओं और 3 पुरुषों जो कि दुबई में निवासरत हैं उनकी समाज सेवाओं हेतु प्रदान किया। इंदौर से एकमात्र समीर शर्मा को इस अवसर पर आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर समीर शर्मा ने सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल पर अपना प्रेसेंटेशन दिया। वर्ल्ड इनवायमेंट डे के अवसर पर इस इवेंट को प्लास्टिक फ्री और डिस्पोसेबल फ्री इंदौर के स्टार्ट अप समीर ने बनाया था।

नाईट-कल्चर को लेकर गोलू शुक्ला ने लिखा सीएम को पत्र

सीएम ने तत्काल एक्शन लेते हुए कलेक्टर आशीष सिंह को दिए निर्देश

इंदौर। विधायक गोलू शुक्ला ने मुख्यमंत्री यादव को एक पत्र लिखकर इंदौर में बढ़ते पब कल्चर नशाखोरी और उसके कारण बढ़ रहे अपराध को लेकर चिंता जाहिर करते हुए एक पत्र लिखा जिसमे उन्होंने इंदौर के गौरव शाली इतिहास और संस्कृति का हवाला देते हुए लिखा की पब कल्चर नाइट कल्चर के बढ़ते प्रभाव से शहर का माहोल खराब हो रहा है और युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है।

साथ ही शांति प्रिय शहर की जनता के मन में भय का माहोल उत्तपन्न हो रहा है। सीएम को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से नाइट कल्चर, के चलते इंदौर में बार और पब, काफी संख्या में खुले हैं, जहां युवा वर्ग का आवागमन बढ़ा है और वे नशे का शिकार हो रहे हैं। इन बार और पबों के कारण विवाद, छेड़खानी और लूटपाट की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। चूंकि, हमारा इंदौर इस नाइट कल्चर, का अभ्यस्त नहीं है। इंदौर का नागरिक वर्षों से सराफा में पूरी रात खाने-खिलाने का आनंद उठा रहा है, किंतु कोई आपराधिक घटना नहीं हुई। जबकि, इस पब कल्चर, के कारण इंदौर शहर की छवि धूमिल होती जा रही है और अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है।

सीएम ने तत्काल एक्शन लेते हुए कलेक्टर आशीष सिंह को दिए निर्देश-विधायक शुक्ला के आग्रह को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को इस संबंध में निर्देशित किया। विधायक शुक्ला ने यह पत्र स्वयं एयरपोर्ट जाकर मुख्यमंत्री को सौंपा। इस अवसर पर विधायक रमेश मेंदोला भी उनके साथ उपस्थित रहे।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)